

मानव अधिकार और भारत का संविधान

परिचय

मानव अधिकार किसी भी मनुष्य को उसके मानव जाति में जन्म के आधार पर उपलब्ध मूल अधिकार हैं। यह सभी मनुष्यों में अपनी राष्ट्रीयता, धर्म, भाषा, लिंग, रंग या किसी अन्य विचार के बावजूद निहित है। मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1993 मानवाधिकारों को परिभाषित करता है: “मानवाधिकार” का अर्थ है, संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्ति की जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार या भारत में अदालतों में अंतर्राष्ट्रीय वाचाएं और प्रवर्तनीय।

देश के लोगों के विकास के लिए मानव अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है, जो अंततः राष्ट्रीय विकास को एक पूरे के रूप में ले जाता है। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को बुनियादी मानवाधिकारों की गारंटी देता है। संविधान के मर्मज्ञों ने आवश्यक प्रावधानों को पूरा करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। हालांकि, निरंतर विकास के साथ, मानव अधिकारों के क्षितिज का भी विस्तार हुआ है। सांसद अब लोगों के अधिकारों को पहचानने और प्रतिमाओं को पारित करने, प्रावधानों को संशोधित करने और आवश्यकता पड़ने पर आदि में एक महान भूमिका निभा रहे हैं।

मानव अधिकारों का विकास

भारत में मानव अधिकारों की उत्पत्ति बहुत पहले हुई थी। इसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के सिद्धांतों से आसानी से पहचाना जा सकता है। हिंदू धार्मिक पुस्तकों और धार्मिक ग्रंथों जैसे गीता, वेद, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में भी मानव अधिकारों के प्रावधान शामिल थे। अकबर और जहाँगीर जैसे मुस्लिम शासकों को उनके अधिकारों और न्याय के लिए बहुत सराहना मिली। शुरुआती ब्रिटिश युग के दौरान, लोगों को कई अधिकारों का बड़ा उल्लंघन करना पड़ा और इसके कारण भारत में आधुनिक मानवाधिकार न्यायशास्त्र का जन्म हुआ।

24 जनवरी, 1947 को, संविधान सभा ने सरदार पटेल के साथ अध्यक्ष के रूप में मौलिक अधिकारों पर एक सलाहकार समिति बनाने के लिए मतदान किया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर, बी.एन. राऊ, के.टी. शाह, हरमन सिंह, के.एम. मुंशी और कांग्रेस विशेषज्ञ समिति द्वारा अधिकारों की मसौदा सूची तैयार की गई थी। हालांकि इसमें कुछ संशोधन प्रस्तावित थे, लेकिन इसमें शामिल सिद्धांतों पर लगभग कोई असहमति नहीं थी। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अधिकार लगभग पूरी तरह से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल थे। उन्नीस मौलिक अधिकारों को मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट, 1928 में शामिल किया गया था, जिसमें से दस मौलिक अधिकारों में दिखाई देते हैं जबकि उनमें से तीन मौलिक कर्तव्य के रूप में दिखाई देते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और मौलिक अधिकार (COI का भाग

III)

भारत ने 01 जनवरी, 1942 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान का भाग III 'जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया है' में मौलिक अधिकार शामिल हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी उल्लंघन के मामले में राज्य के खिलाफ सीधे लागू करने योग्य हैं। अनुच्छेद 13(2) राज्य को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में कोई भी कानून बनाने से रोकता है। यह हमेशा यह प्रदान करता है कि अगर कानून का एक हिस्सा मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो उस हिस्से को शून्य घोषित किया जाएगा। यदि शून्य भाग को मुख्य अधिनियम से अलग नहीं किया जा सकता है, तो पूरे अधिनियम को शून्य घोषित किया जा सकता है।

कशवानंद भारती बनाम केरेला राज्य के मामले में , शीर्ष अदालत ने कहा: “मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन नहीं हो सकती है, लेकिन यह दिखाता है कि भारत ने उस समय मानवाधिकारों की प्रकृति को कैसे समझा, जब संविधान को अपनाया गया था ”

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और अन्य बनाम चंद्रिमा दास और अन्य, के मामले में यह देखा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूडीएचआर को आदर्श आचार संहिता के रूप में मान्यता दी गई है। घरेलू न्यायशास्त्र में जरूरत पड़ने पर सिद्धांतों को पढ़ा जा सकता है।

भारत के संविधान में संबंधित प्रावधानों के साथ मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के प्रावधान निम्नानुसार हैं:

प्रावधान का संक्षिप्त विवरण	यूडीएचआर	सीओआई
कानून के समक्ष समानता और समान सुरक्षा	अनुच्छेद 7	अनुच्छेद 14
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के उपाय	अनुच्छेद 8	अनुच्छेद 32
जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता	अनुच्छेद 9	अनुच्छेद 21
अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण	अनुच्छेद 11(2)	अनुच्छेद 20(1)
संपत्ति का अधिकार	अनुच्छेद 17	इससे पहले अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार
अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार और किसी भी धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करना	अनुच्छेद 18	अनुच्छेद 25(1)
बोलने की स्वतंत्रता	अनुच्छेद 19	अनुच्छेद 19(1)(ए)
सार्वजनिक सेवा के अवसर में समानता	अनुच्छेद 21(2)	अनुच्छेद 16(1)
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा	अनुच्छेद 22	अनुच्छेद 29(1)
शिक्षा का अधिकार	अनुच्छेद 26(1)	अनुच्छेद 21(ए)

राजनीतिक और नागरिक अधिकारों, 1966 (ICCPR) पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा में निहित कई नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी भारत के संविधान के भाग III में निहित हैं। भारत ने ICCPR पर हस्ताक्षर और पुष्टि की है।

जॉली जॉर्ज वर्गिस और अनर के मामले में VI बैंक ऑफ कोचीन , जो कृष्णा अय्यर ने देखा कि हालांकि एक प्रावधान ICCPR में मौजूद है, लेकिन भारतीय संविधान में नहीं है, यह वाचा को भारत में 'कॉर्पस ज्यूरिस' का प्रवर्तनीय हिस्सा नहीं बनाता है।

भारत के संविधान के संगत प्रावधान के साथ ICCPR के प्रावधान इस प्रकार हैं:

प्रावधान का संक्षिप्त विवरण	ICCPR	सीओआई
जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद 6(1) और 9(1)	अनुच्छेद 21
तस्करी और जबरन श्रम पर रोक	अनुच्छेद 8(3)	अनुच्छेद 23
कुछ मामलों में नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण	अनुच्छेद 9(2), (3) और (4)	अनुच्छेद 22
आंदोलन की स्वतंत्रता	अनुच्छेद 12(1)	अनुच्छेद 19(1) (डी)
समानता का अधिकार	अनुच्छेद 14 (1)	अनुच्छेद 14
खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर न होने का अधिकार	अनुच्छेद 14(3)(जी)	अनुच्छेद 20(3)
दोहरे खतरे से सुरक्षा	अनुच्छेद 14(7)	अनुच्छेद 20(2)
पूर्व पोस्ट वास्तविक कानून के खिलाफ संरक्षण	अनुच्छेद 15(1)	अनुच्छेद 20(1)
अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार और किसी भी धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करना	अनुच्छेद 18(1)	अनुच्छेद 25(1) और 25(2)(ए)
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	अनुच्छेद 19(1) और (2)	अनुच्छेद 19(1)(ए)
शांतिपूर्वक विधानसभा का अधिकार	अनुच्छेद 21	अनुच्छेद 19(1) (बी)
संघ / संघ बनाने का अधिकार	अनुच्छेद 22(1)	अनुच्छेद 19(1) (सी)
सार्वजनिक सेवा के अवसर में समानता	अनुच्छेद 25(सी)	अनुच्छेद 16(1)

कानून के समक्ष समानता और समान सुरक्षा और किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं जैसे दौड़, रंग, लिंग, भाषा, धर्म आदि	अनुच्छेद 26	अनुच्छेद 14 और 15(1)
अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण	अनुच्छेद 27	अनुच्छेद 29(1) और 30

कुछ अधिकार जो पहले मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं थे, लेकिन ICCPR में उपलब्ध थे। विभिन्न न्यायिक घोषणाओं द्वारा उन्हें मौलिक अधिकार माना गया। उनमें से कुछ हैं राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू प्राइवैसी, राइट टू लीगल एड, राइट टू राइट टू विदेश यात्रा। मैं इस लेख के बाद के भाग में उनके साथ विस्तार से काम करूंगा।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों (ICESCR) और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (COI का भाग IV) पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा

ICESCR एक बहुपक्षीय संधि है जो मुख्य रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आश्रय आदि पर केंद्रित है। भारत ने 10 अप्रैल, 1979 को इस वाचा का अनुमोदन किया। इस वाचा के अधिकांश प्रावधान भाग IV (DPSPs) में पाए जाते हैं। भारतीय संविधान।

भारत के संविधान के संगत प्रावधान के साथ ICESCR के प्रावधान इस प्रकार हैं:

प्रावधान का संक्षिप्त विवरण	ICESCR	सीओआई
काम का अधिकार	अनुच्छेद 6(1)	अनुच्छेद 41
समान काम के लिए समान वेतन	अनुच्छेद 7(ए)(i)	अनुच्छेद 39(डी)
जीवन यापन और जीवन के लिए वंश मानक का अधिकार	अनुच्छेद 7(ए)(ii) और (d)	अनुच्छेद 43
काम और मातृत्व अवकाश की मानवीय स्थिति	अनुच्छेद 7(बी) और 10(2)	अनुच्छेद 42
बच्चों को शोषण के खिलाफ रोकथाम के लिए अवसर और अवसरा	अनुच्छेद 10(3)	अनुच्छेद 39(f)

सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और पोषण का स्तर और जीवन स्तर में वृद्धि	अनुच्छेद 11	अनुच्छेद 47
बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा	अनुच्छेद 13(2)(ए)	अनुच्छेद 45
अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण	अनुच्छेद 27	अनुच्छेद 29(1) और 30

अनधिकृत मौलिक अधिकार

संविधान के अधिनियमन के समय वाचा में जितने अधिकार उपलब्ध थे, उतने मौलिक अधिकार उपलब्ध नहीं थे। न्यायिक व्याख्याओं ने भारतीय संविधान में उपलब्ध मौलिक अधिकारों के दायरे को चौड़ा किया है।

एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला की अदालत में, शीर्ष अदालत ने देखा था कि भूमि का कानून भारतीय संविधान में विशेष रूप से प्रदान किए गए अन्य प्राकृतिक या सामान्य कानून अधिकारों को मान्यता नहीं देता है।

बाद में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जो भगवती के मामले में; "आर्टिकल 21 में अभिव्यक्ति 'the व्यक्तिगत स्वतंत्रता' व्यापक आयाम की है और इसमें कई तरह के अधिकार शामिल हैं, जो मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करने के लिए जाते हैं और उनमें से कुछ को अलग मौलिक अधिकारों की स्थिति में खड़ा किया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। कोई भी व्यक्ति विदेश जाने के अपने अधिकार से तब तक वंचित नहीं रह सकता, जब तक कि राज्य द्वारा उसे वंचित करने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कोई कानून न हो, और इस तरह की प्रक्रिया के अनुसार वंचित होने पर सख्ती से प्रभाव डाला जाता है।"

वर्तमान मामले के बाद, मौलिक अधिकारों को सक्रिय और सार्थक बनाने के लिए शीर्ष अदालत ने "मुक्ति के सिद्धांत" के साथ पेश किया। साथ ही, 'लोकस स्टैंडी' के नियम में छूट कोर्ट द्वारा दी गई थी। मौलिक अधिकार की कुछ प्रमुख न्यायिक व्याख्याएं इस प्रकार हैं:

अधिकार	निर्णय विधि
मानव सम्मान के साथ जीने का अधिकार	PUCL और अन्य बनाम महाराष्ट्र और अन्य
स्वच्छ वायु का अधिकार	एमसी मेहता (ताज ट्रेपेज़ियम मैटर) बनाम भारत संघ
स्वच्छ जल का अधिकार	एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य
शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार	पुनः शोर प्रदूषण
शीघ्र परीक्षण का अधिकार	हुसैनारा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य

निः शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार	खत्री और अन्य लोग बनाम बिहार और राज्य
आजीविका का अधिकार	ओल्गा टेलिस और अन्य बनाम बंबई नगर निगम
भोजन का अधिकार	किशन पटनायक बनाम ओडिशा राज्य
चिकित्सा देखभाल का अधिकार	पं. परमानंद कटारा बनाम भारत और अन्य संघ
स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार	ग्रामीण अभियोग और प्रवेश केंद्र उत्तर प्रदेश और राज्य के बनाम
एकान्तता का अधिकार	के.एस. पुडुस्वामी और अन्य बनाम भारत और ओआरएस संघ

निष्कर्ष

मानवाधिकार वे मूल अधिकार हैं जो मनुष्य के रूप में उसके विकास का अनिवार्य हिस्सा हैं। संविधान मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के रूप में उन मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है और वे कानून की अदालत में सीधे लागू हैं। भारतीय संविधान के भाग III और भाग IV के एक गहन अध्ययन से, यह आसानी से स्पष्ट है कि UDHR (मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा) में प्रदान किए गए लगभग सभी अधिकार इन दो भागों में शामिल हैं।

न्यायपालिका ने 'लोकस स्टैंडी' के नियमों को शिथिल करने जैसे महान कदम भी उठाए हैं और अब प्रभावित लोगों के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति कोर्ट का रुख कर सकता है। शीर्ष अदालत ने एक नागरिक को उपलब्ध मौलिक अधिकारों की व्याख्या की है और अब निजता के अधिकार, स्पष्ट पर्यावरण के अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार, निष्पक्ष निशान के अधिकार आदि को भी मौलिक अधिकारों में जगह मिलती है।